न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया के समक्ष

नरिंदर कुमार - याचिकार्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 269/1990

6 अगस्त, 1990

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV) - धारा 25-बी, 25-एफ, 25-जी और 25-एच - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226-छंटनी-धारा 25-छ- कार्यक्षेत्र - 'पहले आओ अंतिम पाओ'- धारा 25-जी का उल्लंघन करते हुए छंटनी- कामगार को पुन: नियोजित करना- वापस मजदूरी- की हकदारी के सिद्धांत पर आधारित है।

यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-जी का उल्लंघन करते हुए छंटनी की गई है, लेकिन कामगार को सेवा में वापस ले लिया गया है, तो वह उस अवधि के दौरान वापस मजदूरी का हकदार होगा जब वह सेवा में नहीं था, बशर्ते कि वह कहीं भी लाभप्रद रूप से नियोजित न हो।

(अनुच्छेद 5 और 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

1. दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 के समाप्ति आदेश को निरस्त करने के लिए प्रमाण-पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

2. कि प्रतिवादी नंबर 2 को याचिकाकर्ता को ड्यूटी पर ले जाने का निर्देश दिया जाए।

3. इस बीच समाप्ति आदेश के संचालन पर **रोक लगाई जाए।**

4. प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए।

5. प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस दिया जाए।

6. रिट की लागत प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती आभा राठौर, अधिवक्ता।

रामेश्वर मलिक, वकील, प्रतिवादियों के लिए।

<u>आदेश</u>

<u>न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया-</u>

1. याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर, 1989 के समाप्ति के आदेश को चुनौती दी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में औद्योगिक विवाद अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25-एच के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 को फिर से नियुक्त करने के लिए जनादेश की मांग की है।

2. संक्षिप्त तथ्य:

याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल, 1989 को एक सहायक के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। वह 31 अगस्त, 1989 तक सेवा में बने रहे, जब उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। उन्हें 12 सितंबर, 1989 को फिर से सेवा में लिया गया, लेकिन सेवाओं को 30 सितंबर, 1989 को हटा दिया गया। उन्हें 2 नवंबर, 1989 से 30 नवंबर, 1989 तक फिर से सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कहना है कि उनसे कनिष्ठ व्यक्ति, अर्थात् कर्मबीर, सुरिंदर कुमार, नरिंदर कुमार, रामेश्वर और रामबीर सिंह सेवा में बने हुए हैं, जबकि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 निम्नलिखित को नई नियुक्ति देते हैं: -

1. हसन मोहम्मद, पुत्र श्री बख्शी खा।

2. नफे सिंह. पुत्र श्री बलबीर सिंह।

3. बेद पाल, पुत्र श्री तेज राम।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने प्रतिवादी नंबर 2 की सेवा में 181 दिन पूरे कर लिए हैं। अधिनियम

की धारा 25-बी और 25-एच का उल्लंघन करते हुए बर्खास्तगी की गई है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 ने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया है, लेकिन दलील दी कि वे कार्यशाला में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं और आवश्यकता नहीं होने पर उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित होने के बाद, तीन और व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2। हालांकि, इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले 240 दिनों से कम की सेवा प्रदान की थी, इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 अपनी सेवा समाप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। धारा 25-एफ का प्रावधान लागू नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता केवल 181 दिनों के लिए सेवा में रहा था और सेवा से उसका बंद होना अधिनियम की धारा 2 (ओओ) (बीबी) के तहत परिभाषित छंटनी के बराबर नहीं था।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवा से समाप्ति अधिनियम की धारा 25-जी में निहित प्रावधानों से प्रभावित होती है। अधिनियम की उक्त धारा 'पहले आओ अंतिम पाओ' के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि नियोक्ता के बीच किसी करार के अभाव में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी कर्मकार, जो भारत का नागरिक है, की छंटनी कहां की जाएगी और वह उस प्रतिष्ठान में कामगारों की एक विशेष श्रेणी से संबंधित है? और इस संबंध में कर्मकार, नियोक्ता सामान्यतया उस कर्मकार की छंटनी करेगा जो उस श्रेणी में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नियोक्ता किसी अन्य कामगार की छंटनी न करे।

5. इस मामले में, प्रतिवादी नंबर 2 ने कहा है कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया है, लेकिन उनकी सेवाओं को समाप्त किए जाने की संभावना थी जब जिस उद्देश्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, उसका अस्तित्व समाप्त

हो गया था, लेकिन वास्तव में वे उस दिन सेवा में बने हुए थे जब लिखित बयान दायर किया गया था। नतीजतन, अधिनियम की धारा 25-जी का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। यदि छंटनी अधिनियम की धारा 25-जी का उल्लंघन करते हुए की गई है, तो कामगार वापस मजदूरी के भुगतान का हकदार है, बशर्ते कि पूरी अवधि के दौरान उसे लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं किया गया हो। राजबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[1] में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जहां इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

"किसी कर्मचारी की वैध तरीके से छंटनी की जा सकती है या छंटनी गैरकानूनी हो सकती है। छंटनी को अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से अवैध माना जा सकता है कि धारा 25-जी में निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था या जहां कामगार एक वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा में था, वहां धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। ऐसे मामले में जहां छंटनी अवैध पाई जाती है, कामगार बहाली और वापस मजदूरी के भुगतान का हकदार है, अगर अवधि के दौरान पूरी तरह से नियोजित नहीं किया गया था।

अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या वैध रूप से छंटनी किए गए कामगार को कानून के तहत अधिकार नहीं है? उत्तर हां में है। जबकि वैध रूप से छंटनी किए गए कामगार को अधिकार के रूप में बैकवेज के साथ बहाली की मांग नहीं की जा सकती है, अधिनियम की धारा 25-एच फिर भी उसे पुन: रोजगार के लिए अधिमान्य व्यवहार प्रदान करती है यदि कामगार की छंटनी के बाद दिए गए औद्योगिक प्रतिष्ठान में समान या तुलनीय पद की रिक्ति होती है।

6. याचिकाकर्ता को 22 फरवरी, 1990 को मोशन बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुसार

[1] 1983 (1) एसएलआर 38.

सेवा में वापस ले लिया गया है। वह सेवा में है। नतीजतन, वह उस अवधि के दौरान वापस मजदूरी का हकदार होगा जब वह सेवा में नहीं था, बशर्ते कि वह कहीं भी लाभप्रद रूप से नियोजित न हो। तदनुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा